(d) Of a total of about 10.34 lakh family biogas plants set P, 9.33 lakh were installed through a Central Sector Schcme 'National Project for Biogas Development' launched in 1981-82. Inspection reports received from 21 States/UTs for the period 1S87-88 indicate that on an over-all basis only 14.9 percent cjf the plants inspected are non-functional.

Oil and Natural Gas reserves in Madhya Pradesh

1521. SHRI AJIT P. K. JOGT: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased ta state:

(a) whether there are substantial oil and natural gas reserves in Madhya Pradesh according to the studies made so far;

(b) if so, what are the estimates: and

(c) which are the States, other than the present oil producing States which have substantial oil and natural gas reserves?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PTEROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Tripura and Rajasthan are the other two non oil producing States where substantial gas reserves have been found.

Gas requirement of Maharashtra

1522. SHRI SURESH KALMADT: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government has requested for the sanctioning of 5.6 million cubic metres of gas for the installation of 900 MW gas turbine;

(b) whether M]s. B.S.E.S; has also requested for the sanctioning of two million cubic metres o: gas per day for the setting up of a power station at Dahanu in Maharashtra;

(c) whether M|s. Tata Electric Company has also requested for the sanctioning of gas for power generation in Maharashtra; and •

(d) if so, what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) 1.5 MMCMD of gas has been committed in 1987 on a firm basis to M|s. Tata Electric "Company. As the gas available at Urari has already been committed to various consumers, it would not be possible to make additional commitments of gas at present.

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प की एजेंसियों का आवंटन

1523. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1985 से 30 जून, 1988 की अवधि के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा पेट्रोल पम्प की एजेंसियों के आवंटन के मामले में उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार उक्त वर्ग के लोगों को डीलरशिप देने की वर्तमान नीति की समीक्षा करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार वर्तमान नीति की प्राप्ति से संतुष्ट है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क)

1-11-85 से 30-6-88 तक की अवधि दौरान उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 12 व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिप दी गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता

1524. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली की अनुमानित मांग कितनी है और इसके अगले तीन वर्षों के प्राक्कलन क्या हैं ;

(ख) राज्य में बिजली का वर्तमान उत्पादन कितना है और आवश्यकता के मुकाबले में कमी कितनी है; और

(ग) मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में अप्रैल से जुलाई, 1988 की अवधि के दौरान ऊर्जा की मांग 8040 मिलियन यूनिट थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान ऊर्जा की अनुमानित मांग क्रमश: 25053 मिलियन यूनिट, 27240 मिलियन यूनिट तथा 30053 मिलियन यूनिट होने की आशा है।

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1988 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 6991 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी जिसके परिणामस्वरूप 1049 मिलियन यूनिट की कमी रही (लगभग 13%)।

(ग) विद्युत की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें ये शामिल हैं—नई क्षमता शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम सदुपयोजन करना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबंध संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

Calculation of amount over charges by drug; companies

1525. DR. BAPU KALDATE:

DR. (SHRIMATI) SAROJINT MAHISHI:

SHRI DAYANAND SAHAY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Starred Question 281 given in the Rajya Sabha on the 17th August, 1987 and state:

(a) what are "the details of the pleas made by his Ministry for direction of the Supreme Court against the drug companies whose cases were decided;

(b) what are the details of undertakings given by the drug companies in the High Courts;

(c) whether it is a fact that the amount calculated against each Company as being overcharged is in accordance with the undertakings; and

(d) if so, what are the basis of calculation of the amount overcharged by the drug companies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) The Division bench of Delhi High Court passed an Order on 25.11.1981 requiring each company to deposit the difference in the prices charged by them and the prices fixed by the Government within 8 weeks in ease of dismissal of their petitions. The orders were passed on the basis of undertaking given by individual petitioner company themselves. The Hon'ble Suupreme Court in its judge-